

मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गति-शक्ति योजना
के अंतर्गत गठित EGoS की समीक्षा बैठक
दिनांक 17.11.2022 का कार्यवाही विवरण

33
358

मुख्य सचिव महोदय, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2022 को अपराह्न 3.30 बजे प्रतिकक्ष क्रमांक एस-4/23 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर में पीएम गतिशक्ति योजना की समीक्षा हेतु EGoS (Empowered Group Of Secretaries) की बैठक संपन्न हुई। बैठक ऑनलाईन एवं ऑफलाईन मोड में संपन्न हुई। बैठक में सम्मिलित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट -अ में संलग्न है। बैठक में निम्नानुसार विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :-

● **भू-अभिलेख के Geo Referencing हेतु समयबद्ध कार्ययोजना का निर्माण -**

राज्य के भू-अभिलेखों के Geo Referencing किये जाने के संबंध में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि चिप्स द्वारा उपरोक्त कार्य में होने वाले व्यय का आंकलन कर प्रस्ताव विभाग को दिया गया है जो विचाराधीन है। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बैठक में बताया गया कि Geo Referencing का कार्य 08 माह में पूर्ण होने की संभावना है।

उपरोक्त संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिये गये कि चूंकि Geo Referencing के कार्य का प्रशासकीय स्वीकृति लंबित है। अतः राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वित्त विभाग एवं चिप्स पृथक से बैठक कर समन्वय स्थापित करते हुये कार्य को समयसीमा में पूर्ण करें।

(कार्यवाही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वित्त विभाग एवं चिप्स)

● **भू-अभिलेख/रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण कार्यक्रम संबंधी चर्चा -**

सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बैठक में भू-अभिलेख/रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के संबंध में बताया गया कि भारत शासन द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु फण्ड की प्राप्ति हो चुकी है। चिप्स द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स द्वारा बताया गया कि 01 सप्ताह के भीतर डी.पी. आर तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जावेगा।

(कार्यवाही - राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं चिप्स)

● **बेसिक लेयरों पर चर्चा -**

(1) **सीवर लाईन** - नोडल अधिकारी पीएम गति शक्ति द्वारा बैठक में सीवर लाईन के पोर्टल में अपलोड किये जाने संबंधी चर्चा की गई। इस संबंध में मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि बिलासपुर जिले में उपस्थित सीवर लाईन का डाटा 07 दिवस के भीतर तैयार कर BISAG-N को भेजा जावेगा एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) का डाटा तैयार कर BISAG-N को नवंबर माह में ही प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

(2) **ड्रेनेज**- नोडल अधिकारी पीएम गति शक्ति द्वारा बैठक में बताया गया कि राज्य के ड्रेनेज का आंशिक डाटा पोर्टल में अपलोड किया जा चुका है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि ड्रेनेज के Geo Referencing डाटा हेतु BISAG-N से संपर्क कर मोबाईल एप्लीकेशन तैयार करवाया जा रहा है। एप्लीकेशन के निर्माण पश्चात् Geo Referencing डाटा तैयार कर BISAG-N को प्रेषित किया जावेगा। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सर्वप्रथम 14 नगर निगमों के बड़े नालों का डाटा तैयार कर शीघ्र अपलोड कराया जावे।

(कार्यवाही - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

(3) वाटर सप्लाई पाईप लाईन— नोडल अधिकारी पीएम गति शक्ति द्वारा बैठक में बताया गया कि वाटर सप्लाई पाईप लाईन का आंशिक डाटा पोर्टल में अपलोड किया जा चुका है। इस संबंध में मोबाईल एप्लीकेशन हेतु BISAG-N से संपर्क किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि रायपुर जिले के वाटर सप्लाई पाईप लाईन का Geo Referce डाटा उपलब्ध है जिसे BISAG-N से साझा कर अपलोड किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। मुख्य सचिव, महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) के पास उपलब्ध वाटर सप्लाई पाईप लाईन की जानकारी भी पोर्टल में अपलोड की जावे। अतः अगली बैठक में (PHE) को भी सम्मिलित किया जाये।

(कार्यवाही – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)।

(4) ट्रैफिक सिग्नल— नोडल अधिकारी पीएम गति शक्ति द्वारा बैठक में बताया गया कि रायपुर एवं बिलासपुर जिले के ट्रैफिक सिग्नल का डाटा पोर्टल में अपलोड किया जा चुका है। मुख्य सचिव, महोदय द्वारा गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले ट्रैफिक सिग्नल का डाटा साझा करने के निर्देश दिये गये।

उप सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा बैठक में सलाह दी गई कि राज्य के ट्रैफिक सिग्नल, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई पाईप लाईन इत्यादि डाटा चूकि पोर्टल में अपलोड किये जा चुके हैं अतः दूरसंचार मंत्रालय, भारत शासन से संपर्क कर 5G नेटवर्क के पायलट प्रोजेक्ट में राज्य का सम्मिलित किया जावे।

(कार्यवाही – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा गृह विभाग)

(5) बैंक— नोडल अधिकारी पीएम गति शक्ति द्वारा बैठक में बताया गया कि राज्य के समस्त बैंक ब्रांचों की जानकारी पोर्टल में अपलोड की जा चुकी है। संचालक, वित्त संस्थान द्वारा बताया गया कि Bank Potential area की जानकारी भी BISAG-N से साझा की जा चुकी है।

(6) पेट्रोल/डीजल आउटलेट — नोडल अधिकारी पीएम गति शक्ति द्वारा बैठक में बताया गया कि इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से पत्राचार किया जा चुका है एवं विभाग द्वारा इस हेतु नोडल अधिकारी का नामांकन भी प्राप्त हो चुका है। विभाग द्वारा बताया गया कि 600 से अधिक पेट्रोल एवं डीजल आउटलेट का डाटा यथा शीघ्र साझा किया जावेगा।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा उप सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग को सलाह दी गई कि यदि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास यह जानकारी उपलब्ध हो तो केन्द्र शासन स्तर से डाटा अपलोड करवाया जावे। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदय द्वारा बैठक में यह सलाह भी दी गई कि यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्थान पर सीधे तेल कंपनियों के SLC को दिया जावे।

(कार्यवाही – खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा SLC IOCL, SLC HINDUSTAN PETROLIUM)।

(7) सरकारी कार्यालय — नोडल अधिकारी पीएम गति शक्ति द्वारा बैठक में बताया गया कि इस संबंध में BISAG-N से मोबाईल एप्लीकेशन तैयार कर TSU के सदस्यों से साझा किया जा चुका है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों की जानकारी पोर्टल में अपलोड की जा चुकी है।

मुख्य सचिव, महोदय द्वारा इस संबंध में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में Inventory तैयार कर जिले के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का डाटा अपलोड कराये जाने के निर्देश दिये

गये।

(कार्यवाही – जिला कलेक्टर)।

(8) बस शेल्टर/टर्मिनल – नोडल अधिकारी पीएम गति शक्ति द्वारा बैठक में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में उपस्थित बस शेल्टर/टर्मिनल की जानकारी पोर्टल में अपलोड की जा चुकी है एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी अपलोड किया जाना शेष है

(कार्यवाही – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा गृह विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)।

- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के प्रस्ताव पर चर्चा –

नोडल अधिकारी पीएम गति शक्ति द्वारा बैठक में बताया गया कि PMU (11.66 करोड़) का प्रस्ताव DPIIT की स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक दिनांक 10.11.2022 को प्रस्तुत किया गया। DPIIT द्वारा उक्त प्रस्ताव पर असहमति दर्शाते हुये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप प्रोजेक्ट, वेयर हाउसिंग, इकोनॉमिक जोन, क्लस्टर एवं कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देने वाले प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का सुझाव दिया गया है।

उप सचिव, महोदया, DPIIT भारत शासन द्वारा इस संबंध में सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग से उच्च स्तरीय बैठक करने की सलाह दी गई।

- राज्य मास्टर प्लान का निर्माण –

नोडल अधिकारी पीएम गति शक्ति द्वारा बैठक में बताया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप प्रोजेक्ट एवं लॉजिस्टिक को गति प्रदान करने वाले प्रोजेक्ट तैयार कर राज्य मास्टर प्लान का निर्माण किया जाना है।

मुख्य सचिव, महोदय द्वारा छ.ग. राज्य सड़क विकास निगम के अंतर्गत सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट, जल संसाधन विभाग के कैनल के प्रोजेक्ट एवं चिप्स के अंतर्गत भारत नेट (यदि यह प्रोजेक्ट नेशनल मास्टर प्लान का हिस्सा न हो) के प्रोजेक्ट को स्टेट मास्टर प्लान में सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये।

- राज्य के विभिन्न विभागों के आवश्यक डाटा को पोर्टल में अपलोड किया जाना –

नोडल अधिकारी पीएम गति शक्ति द्वारा विभागों से अपलोड किये जाने वाले डाटा लेयर की जानकारी दी गई जो निम्नानुसार है :-

क्रमांक	डाटा लेयर	संबंधित विभाग
1	एयरपोर्ट/ऐरो ड्रम/एयर स्ट्रीप/हैलीपैड	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उड्यन निर्देशालय
2	राज्य की समस्त सड़के	नगरीय प्रशासन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3	रूलर इण्डस्ट्रियल पार्क	ग्रामोद्योग विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4	वेयर हाऊस/गोडाउन	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
5	अस्पताल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6	आंगनवाड़ी, सखी (वन स्टाप सेंटर)	महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग
7	पुलिस स्टेशन	गृह विभाग

8	कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र	छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण।
9	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय	तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग
10	जिलेवार प्रमुख उत्पादों की जानकारी	कृषि विभाग, उद्यानिक विभाग
11	पॉवर जनरेशन सेंटर (परम्परागत/गैर परम्परागत स्रोत)	ऊर्जा विभाग
12	वृहद/मेगा/एल्ट्रा मेगा उद्योगों की जानकारी	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
13	स्टेडियम/स्पोर्ट कोर्ट/स्पोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	खेल एवं युवा कल्याण विभाग
14	कंटेनर फ्रीट स्टेशन	CONCOR

389
206

- मुख्य सचिव, महोदय द्वारा एयर पोर्ट/ऐरोड्रम/एयर स्ट्रीप/हैलीपैड की जानकारी राज्य एवीऐशन विभाग द्वारा साझा किये जाने के निर्देश दिये गये।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली समस्त सड़कों की जानकारी यथा शीघ्र BISAG-N से साझा की जावेगी।
- चिप्स द्वारा बैठक में बताया गया कि 2018 तक के स्कूल का डाटा पोर्टल में अपलोड किये जाने हेतु उपलब्ध है अतः इसे यथाशीघ्र BISAG-N से साझा किया जावेगा।
- मुख्य सचिव, महोदय द्वारा सभी विभागों से यथा शीघ्र नोडल अधिकारी नामांकित कर नोडल विभाग से संपर्क करने के निर्देश दिये।
- नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गति शक्ति द्वारा विभागों को अवगत कराया गया कि विभाग अपनी आवश्यकतानुसार BISAG-N एवं नोडल विभाग से संपर्क कर मोबाईल एप्लीकेशन का निर्माण कर सकते हैं।
- मुख्य सचिव, महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी विभागों से नोडल अधिकारी नियुक्ति पश्चात् उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाये।
- मुख्य सचिव, महोदय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अपलोड किये जाने वाले समस्त डाटा लेयर्स की यूनिट निर्धारित की जाये तत्पश्चात् निर्धारित यूनिट के पूर्णता की प्रगति की अद्यतन स्थिति की चर्चा की जावे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनुमोदित)

(हिम शिखर गुप्ता)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग